

नोएडा व्यूज

● नोएडा ● ग्रेटर नोएडा ● दादरी ● जेवर

स्कूल प्रबंधन
नहीं कर रहे
कोविड नियमों
का पालन



► 4

ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो दौड़ाने की तैयारी

**यह पूरा रूट साढ़े नौ किलोमीटर लंबा होगा।
जिस पर 1125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे**

नोएडा, संवाददाता

राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अब जल्द ही मेट्रो के काम रफ्तार पकड़ेगा। अभी तक नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट आचार संहिता के वजह से फाइलों में ठप पड़ा था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के बीच एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार होगा। इस पर तेजी से काम चल रहा है।

इसकी तैयारी नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) प्रबंधन ने पूरी कर ली है। परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के कुछ बिंदुओं पर केंद्र सरकार ने जानकारी मांगी है। इस पर राज्य सरकार से अनुमोदन लेकर एक्वा लाइन का विस्तार शुरू कराया जाएगा।

मेट्रो विस्तार से नोएडा के दो लाख और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले करीब पांच लाख लोगों को राहत मिलेगी। पहले चरण में नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन स्थित सेक्टर-2 तक मेट्रो लाइन का निर्माण कराया जाएगा।

इसमें दो स्टेशन नोएडा सेक्टर-122, 123 होंगे, जबकि ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर-4, सेक्टर-12 इकोटेक और सेक्टर-2 स्टेशन होगा। यह पूरा रूट साढ़े नौ किलोमीटर लंबा



अब प्राइवेट प्रैक्टिस सरकारी चिकित्सकों को पड़ेगी भारी

नोएडा, संवाददाता। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कालेज में तैनात दो वरिष्ठ चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप में निलंबन के बाद से जिले के सरकारी चिकित्सकों में खलबली मची है। इस केस के सहारे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे चाइल्ड पीजीआई, जिम्स, जिला अस्पताल के साथ सीएचसी, पीएचसी के चिकित्सक भी निशाने पर आए हैं। खुफिया टीम इनकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। जल्द संबंधित अस्पताल के प्रमुखों की ओर से चिकित्सकों से प्राइवेट प्रैक्टिस न करने का शपथ पत्र लिया जाएगा। चाइल्ड पीजीआई के निदेशक डा. अजय सिंह का कहना है कि सरकारी चिकित्सक द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करना गैरकानूनी है। शिकायत पर कार्रवाई होगी। जिला अस्पताल की सीएमएस डा. सुषमा चंद्रा का कहना है कि अगर कोई चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने की शिकायत करता है तो संबंधित व्यक्ति का नाम गुप्त रखकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। सीएमओ डा. सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि चिकित्सक के प्राइवेट प्रैक्टिस करने की जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। चिकित्सकों को मिलता है नान प्रैक्टिसिंग एलाउंस : शहर के सैकड़ों सरकारी चिकित्सक नान प्रैक्टिसिंग एलाउंस (एनपीए) ले रहे हैं, लेकिन बाहर कमाई के लिए धड़ल्ले से प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसलिए शासन स्तर से खुफिया टीम सरकारी अस्पतालों के आर्थोपेडिक, गायनी, सर्जरी, ईएनटी, रेडियोलॉजी, बाल रोग, मेडिसिन के कुछ चिकित्सकों के दिन के साथ शाम 6 से 10 के बीच की रिपोर्ट तैयार कर रही है।

होगा। जिस पर 1125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित मेट्रो परियोजना के तहत नौ किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जाएगा। इस नौ किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभी करीब आधे घंटे से पौने घंटे का समय लगता है। मेट्रो संचालन के बाद करीब 20 मिनट का समय लगेगा। अभी यहां से

सार्वजनिक वाहन के रूप में आटो, कैब और बुकिंग आटो पर निर्भर रहना पड़ता है।

एक्वा लाइन के स्टेशनों पर चलाए जाएंगे ई-रिक्शा

एक्वा लाइन में कुल 21 मेट्रो स्टेशन हैं। इन सभी

स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अब जल्द ही ई-रिक्शा चलाने जाएंगे। इसके लिए नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन जल्द टेंडर जारी करेगा। इसका किराया कितना होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि किलोमीटर के हिसाब से यात्रियों को ई-रिक्शा को भुगतान देना होगा।

BRANDS

Park Plaza

chicago pizza
big slices, really fast

LIBERTY

KEVENTERS
The Original Milkshakes

And Many More

GLOBAL BUSINESS SQUARE
A Vision of your life...

जल्द ही पजेशन पाए

ऑफिस 10 लाख और दुकान 15 लाख से शुरू

प्रीमियम लोकेशन पे दुकान और ऑफिस खरीदें



**निर्माण कार्य
पूर्ण जोरो पे**

FOR BOOKING : 7290087008

APPROVED: RERANO. UPRERAPR367

Site Office : C-10, Sector-Delta-1, Wipro Chowk, Greater Noida-201306

संपादकीय

कार बाजार का आईना

यह देश के उपभोग स्तर में एक तरफ भारी गिरावट को बताता है। एंड्री लेवल के कार वो परिवार खरीदते हैं, जिनके परिवहन का जरिया उसके पहले दोपहिया वाहन थे। यही लोग सस्ती कारें खरीदते हैं। कार बाजार के मौजूदा ट्रेंड का संदेश यह है कि ऐसे लोगों की स्थिति कमजोर पड़ गई है।

भारत के कार बाजार की जो तस्वीर अब सामने आई है, वह असल में भारत की आज की अर्थव्यवस्था का आईना है। खबर यह है कि एंड्री लेवल यानी शुरुआती रेंज की कारों का बाजार तेजी से घट रहा है। 2012 में कुल कार बाजार में इस दर्जे की कारों का हिस्सा आधा था। अब एक तिहाई बचा है। 2016-17 में ऐसी कुल 31 ब्रांड की कारें बाजार में थीं। अब 19 बची हैं। दरअसल, तीन कंपनियों मारुति, हुंदै और टाटा को छोड़ कर बाकी लगभग सभी कंपनियों ने इस सेगमेंट की अपनी कारों को या तो बाजार से समेट लिया है, या समेटने का एलान कर चुकी हैं। दूसरी तरफ एसयूवी कारों का हिस्सा बढ़ा है। तो यह ट्रेंड किस बात का सूचक है? यह असल में देश के उपभोग स्तर में एक तरफ भारी गिरावट और दूसरी तरफ बढ़ती समृद्धि को बताता है। एंड्री लेवल के कार वो परिवार खरीदते हैं, जिनके परिवहन का जरिया उसके पहले दोपहिया वाहन थे। जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो वे सस्ती कारें खरीदते हैं। कार बाजार के मौजूदा ट्रेंड का संदेश यह है कि ऐसे ग्रोथ की परिघटना कमजोर पड़ गई है। तमाम दूसरे आर्थिक संकेतक इस बात का पहले से संकेत देते रहे हैं। क्रमिक विकास का यह क्रम वर्तमान सरकार के कुछ नीतिगत दुस्साहसों से टूटा।

नोटबंदी, उलझी हुई जीएसटी और कोरोना काल में अचानक-अनियोजित लॉकडाउन ने आम परिवारों की अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद हुई रिकवरी अंग्रेजी के अक्षर के जैसी रही है। यानी एक रेखा बिल्कुल ऊपर की तरफ है और दूसरी रेखा नीचे की तरफ। धन का संचयन ऊपर की तरफ होता गया है। अब जो महंगाई का दौर आया है, उसमें ये परिघटना और मजबूत होगी। 2021-22 में थोक भाव मुद्रास्फीति 12.96 फीसदी रही, जो 1991-92 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। बीते मार्च में ये दर 14 प्रतिशत को भी पार कर गई। यानी ये दर काफी ऊंची है। ऐसे में खुदरा मुद्रास्फीति दर में गिरावट की कोई संभावना नहीं हो सकती। इतनी ऊंची महंगाई का मतलब लोगों की वास्तविक आय में गिरावट होता है। तो जब लोगों की सारी आय आटा-चावल खरीदने में खर्च हो जाएगी, तो फिर वे टूट्टीलर या कार खरीदने को सोच भी कहां पाएंगे?

सतर्क होने की जरूरत

भारत को चीन में बनी हालत से सबक लेना चाहिए। कुछ महीनों पहले तक चीन की जीरो कोविड नीति अपनी सफलता के लिए जानी जाती थी। लेकिन अब वहां 40 से भी ज्यादा शहरों में पूरा या आंशिक लॉकडाउन लागू है। शंघाई में लागू कोविड लॉकडाउन के दौरान तीन लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी की नई लहर आने का संकेत हर रोज पुख्ता होता जा रहा है। जब पोजिटिविटी रेट में तेज बढ़ोतरी होने लगे, तो मतलब साफ है कि संक्रमण फैल रहा है। दिल्ली में दो हफ्तों के अंदर पोजिटिविटी रेट आधा फीसदी से बढ़ते हुए पौने आठ प्रतिशत तक पहुंच गई है। दूसरे कई राज्यों में भी ऐसा ही ट्रेंड है। हैरतअंगेज है कि इसके बावजूद खतरे की घंटी उस तरह नहीं बज रही है, जैसा अब तक हो जाना चाहिए था। दिल्ली में तो सोमवार तक मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं किया गया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक फुर्ती दिखाई है, जिसने लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा समेत कई जिलों में मास्क की अनिवार्यता लागू कर दी है। भारत को असल में चीन में बनी हालत से सबक लेना चाहिए। कुछ महीनों पहले तक चीन की जीरो कोविड नीति अपनी सफलता के लिए जानी जाती थी। लेकिन अब वहां 40 से भी ज्यादा शहरों में पूरा या आंशिक लॉकडाउन लागू है। पिछले महीने शंघाई में लागू किए गए कोविड लॉकडाउन के दौरान तीन लोगों की मौत हो चुकी है। यहां हर दिन हजारों लोग कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं।

शंघाई में हुई ताजा मौतों से पहले चीन में कोविड-19 की वजह से आखिरी मौत 19 मार्च को उत्तर-पूर्वी जिलिन प्रांत में दर्ज की गई थी। वो तकरीबन एक साल से ज्यादा के वक्त में पहली मौत थी। चीन जीरो कोविड नीति के तहत सख्त लॉकडाउन पर जोर देता आया है। हर दिन बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट और लंबे समय के लिए लोगों को क्वारंटीन करके चीन ने अपने देश में बीमारी को बड़े पैमाने पर फैलने से रोका था। ये तब की बात है जब पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही थी।

लेकिन अब ये नीति भी चीन को कोरोना संक्रमण के फैलाव से बचाने में नाकाम होती नजर आ रही है। चीन के हांगकांग में कोविड 19 के जनवरी में सिर उठाने के बाद अब तक नौ हजार लोगों की मौत दर्ज हो चुकी है। उधर अमेरिका से भी खबर है कि वहां महामारी का नया दौर आने के तमाम संकेत हैं। वहां कई राज्यों ने मास्क की अनिवार्यता लागू कर दी है। साफ है, महामारी अभी कहीं गई नहीं है। यह घूम-फिर कर लौट रही है। भारत को इससे आगाह रहना चाहिए।



कपिल कुमार
संपादक, नोएडा व्यूज

एंड्री लेवल के कार वो परिवार खरीदते हैं, जिनके परिवहन का जरिया उसके पहले दोपहिया वाहन थे। जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो वे सस्ती कारें खरीदते हैं। कार बाजार के मौजूदा ट्रेंड का संदेश यह है कि ऐसे ग्रोथ की परिघटना कमजोर पड़ गई है। तमाम दूसरे आर्थिक संकेतक इस बात का पहले से संकेत देते रहे हैं। क्रमिक विकास का यह क्रम वर्तमान सरकार के कुछ नीतिगत दुस्साहसों से टूटा। नोटबंदी, उलझी हुई जीएसटी और कोरोना काल में अचानक-अनियोजित लॉकडाउन ने आम परिवारों की अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद हुई रिकवरी अंग्रेजी के अक्षर के जैसी रही है।

चिंतन: शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति की विविधता देश का प्रतिनिधित्व करते हैं



संजीव ठाकुर

वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश की पहचान और उसका महत्व देश

की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, संस्कारों में अंतर्निहित ज्ञान और देश की सांस्कृतिक विविधता से ही होती है। इसके पश्चात प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एवं विज्ञान, तकनीकी एवं व्यापारिक क्षमता से देश की स्थिति का आकलन होता है। किसी भी राष्ट्र की आधारशिला उस राष्ट्र की संस्कृति, शिक्षा, संस्कार और ज्ञान की कसौटी ही होते हैं। शिक्षित नागरिक ही महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और संस्कृति, संस्कार उसे समृद्ध देश बनाते हैं। राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज का नवजात शिशु कल का सफल नागरिक होता है, उसकी शिक्षा-दीक्षा और संस्कार से ही देश की सफलता निर्भर होती है। कक्षा की पिछली सीट पर बैठे किसी आईस्टीन की तलाश के लिए पारखी की नजरों की आवश्यकता होती है। जिसे नकारा घोषित कर विद्यालय से निकाल दिया जाता है, वही बालक आगे चलकर युग परिवर्तनकारी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत दे जाता है।

उसकी रुचि किस क्षेत्र में ज्यादा है, और वह जीवन में इस क्षेत्र में आगे बढ़ कर एक सफल इंसान और समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, और वह खेल, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान में कितना अपनी शक्ति और क्षमता के हिसाब से क्या प्रदर्शन कर सकता है। माता-पिता को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे जबरिया डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या अधिकारी बनाने की बजाय उसकी रुचि हो, को कैरियर चुनने की आजादी देने में मदद करनी चाहिए।

न्यूटन के गति के सिद्धांत हमारे जिंदगी को द्रुतगति से आगे की ओर अग्रसर करते हैं। यह ऐसे बालक जो आगे चलकर बनी बनाई परंपरा तथा लीक से हटकर चलते हैं, और परंपराओं पर गहरी चोट करते हैं। जो समाज से सुना, उसे सुनकर रह नहीं जाते हैं, और जो समाज में उसने देखा, सिर्फ देख कर नहीं रह जाते हैं, बल्कि देख सुनकर उस पर चिंतन मनन कर नई धारणा तथा सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। हमें इन महान बालकों को गरीब बस्तियों से लेकर गली मोहल्ले और शहरों में खोजना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलीन कि अपनी राय है कि बिना वैचारिक स्वतंत्रता के बुद्धि जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। हम वर्तमान में जिस समाज में हैं और जिस समाज से हमने सभ्यता का विकास की शुरुआत की है, उसका जब सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि अपनी आजादी के तमाम तामझाम बनाने वाला इंसान दिन प्रतिदिन अपनी की बनाई दुनिया के बोझ तले गुलाम होता जा रहा है। हमारी

शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, कि बचपना बस्ते के बोझ तले दबता चला जा रहा है। हमारी शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने के बजाय उसकी नैसर्गिक रचनात्मक प्रतिभा को उभार कर जीवन उपयोगी बनाएं। बच्चों का मूल्यांकन सिर्फ इसी आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, बल्कि देखा जाना चाहिए कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में ज्यादा है, और वह जीवन में इस क्षेत्र में आगे बढ़ कर एक सफल इंसान और समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, और वह खेल, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान में कितना अपनी शक्ति और क्षमता के हिसाब से क्या प्रदर्शन कर सकता है। माता-पिता तथा अभिभावकों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे जबरिया डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या अधिकारी बनाने की बजाय उसकी रुचि हो को महेनजर रखकर उसका कैरियर चुनने की आजादी देने में मदद करनी चाहिए।

क्या आप अपने बच्चों को टॉपर बनने के लिए फोर्स करते हैं!



डा. माधवी बोरसे

जी अगर आप अपने बच्चे को, टॉपर बनने के लिए फोर्स करते हैं, उनको बार-बार डांटते हैं, फटकारते हैं, तो मत कीजिए! जरूरी यह है, की उन्हें अपनापन

मिले, साथ ही साथ में प्यार मिले, उन्हें कैरियर के साथ-साथ, अपनों की अहमियत भी समझाइए, ऐसा ना हो कि जब वह बड़े हो जाए, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सिर्फ अपना कैरियर ही रह जाए!

जब वह बड़े हो जाते हैं, हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठे, हमारे साथ कुछ वक्त बिताए, पर सोचिए, जब वह छोटे थे, आप निरंतर अपने कार्यों में व्यस्त थे और उन्हीं भी आपने समय ना देते हुए, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन, स्कूल और बहुत सी एक्टिविटीज में व्यस्त कर दिया! उनकी आदत, आपने स्वयं बना दी, अब जब बड़े हो गए, तो जो वह सीखें उन्होंने भी वैसा ही व्यक्तित्व एवं व्यस्तता का निर्माण किया! अब हम अपेक्षा करें, कि वह हमारे साथ कुछ बात करें, समय बिताए, तो क्या यह सही है? जब आप वृद्ध हो जाते हैं, जितनी आपको जरूरत होती है, कि आपके साथ कोई समय बिताए वैसे ही एक छोटे बच्चों को भी, आवश्यकता होती है उनके माता-पिता उनके साथ समय बताएं! कोशिश कीजिए, जब आपको आपके बच्चे अपनी स्कूल की किताबों की कहानी सुनाएं तो आप सुने, कभी आप उन्हें कहानी सुनाएं, कभी कुछ

एक्टिविटीज घर में करिए, कभी-कभी साथ में खेले, कोशिश कीजिए बहुत से कार्य को खेल-खेल में, हंसी खुशी, एक वक्त साथ में बिताते हुए उनको बड़ा करें! जीवन में, धन, करियर, शिक्षा के साथ साथ, अपनों का साथ भी जरूरी होता है! अगर आप उनको टॉपर बनने के लिए फोर्स करते हैं, हो सकता है, उनके अंदर कोई कला, रुचि, या बहुत से विचार हैं, जो शायद हार जाएंगे! उनका साथ दीजिए, उन्हें कहिए हमें अच्छे अंक लाने हैं, कोशिश करनी है, जरूरी नहीं कि टॉप ही करें, पर हारना नहीं है और अगर हार भी गए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ! यह विश्वास दीजिए, बहुत से बच्चे इसी डिप्रेशन और इस प्रेशर में आकर कभी-कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं! जीवन में हम हर चीज में टॉपर हो ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमें हार और जीत अवश्य मिलती है! पर अगर मन हारा तो सब हारा! हमारा मानसिक संतुलन, मानसिक विकास, स्वास्थ्य आदि पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है! हमें बच्चों की खुशी का ध्यान रखना, अत्यंत आवश्यक है, स्वयं के लिए, समाज के लिए, उनके खुद के लिए! बहुत बार, बच्चे पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं पर स्पोर्ट्स में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं होती, अपनों के साथ बैठकर दो बातें करने में उन्हें तकलीफ होने लगती है! जीवन में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है, देखिए कहीं उनका स्वास्थ्य तो नहीं नजरअंदाज हो रहा है, नजरअंदाज होने से यह तात्पर्य है, कहीं उनकी शारीरिक गतिविधियां तो नहीं कम हो रही है, मानसिक विकास के साथ-साथ, शारीरिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है और वह शारीरिक गतिविधियों से ही होती है ना कि पूरे दिन चारदीवारी में बैठकर किताबें पढ़ने से।

ना माना योगी सरकार का ये फरमान तो जाना पड़ सकता है जेल

नोएडा। तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस सख्त हो गई है। शासन से आदेश आने के बाद सेक्टर-39, दादरी, बीटा दो व कई अन्य थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार देर रात शादी समारोह में तेज आवाज में गाने बजा रहे 18 संगीत वाहनों को सीज कर दिया। एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी ध्वनि प्रदूषण से संबंधी निर्देशों के अनुपालन में गाइडलाइन के संबंध में धार्मिक स्थल, मैरिज होम आदि स्थानों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर, संगीत व साउंड प्रदूषण की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा धर्मगुरु, मैरिज होम मालिकों व तेज संगीत बजाने वाले संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे। दो संगीत सेट सेक्टर-104, एक कांशीराम कालोनी सदरपुर, एक सेक्टर-45 व एक सेक्टर-41 के पास से सीज किए गए हैं।

स्वास्थ्य: नोएडा के 2433 बेसिक शिक्षकों को जल्द मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

कैबिनेट बैठक में 100 दिवसीय कार्ययोजना में इस सुविधा को शामिल करने के बाद जनपद के शिक्षकों में खुशी की लहर

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता।

बेसिक शिक्षा विभाग 2,433 शिक्षकों को जल्द ही मुख्यमंत्री योगी कैशलेस उपचार की सुविधा देने जा रहा है। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में 100 दिवसीय कार्ययोजना में इस सुविधा को शामिल करने के बाद जनपद के शिक्षकों में खुशी की लहर है। मांग को पूरा होता देख शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं है।

बेसिक शिक्षक की प्रमुख मांगों में पुरानी



पेंशन बहाली के साथ-साथ कैशलेस उपचार की सुविधा भी शामिल थी। इन मांगों को लेकर वर्षों से शिक्षक आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षकों की कैशलेस उपचार की मांग को अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिवसीय

कार्ययोजना में शामिल कर लिया है, जिससे शिक्षकों में खुशी का माहौल है। शिक्षक मुख्यमंत्री योगी के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं।

शिक्षिका नीतू पाठक ने कहा कि सरकार

ने हमारे लिए भी सोचा ये बड़ी बात है। इस सुविधा से लाखों शिक्षकों को राहत मिलेगी।

शिक्षक हेमराज शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाखों शिक्षकों के दर्द को समझा है। शिक्षक वर्ग सरकार के इस निर्णय से काफी खुश है। वहीं शिक्षिका स्मिता सिंह ने कहा कि 100 दिवसीय कार्ययोजना में कैशलेस उपचार को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी का आभार, जल्द ही इसके लिए शासनादेश जारी होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षक संघ दनकौर के ब्लाक अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के लिए सीएम ने जो कैशलेस उपचार की घोषणा की है। सभी उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री से मांग है कि पुरानी पेंशन भी बहाल की जाए।

सूरजपुर, घंघौला में शुरु हुआ जलभराव का समाधान



नोएडा व्यूज संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले गांव सूरजपुर एवं घंघौला में मूलभूत समस्याओं एवं तालाब ओवरफ्लो की समस्या के कारण ग्रामीण परेशान थे जिस समस्या के समाधान हेतु करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर हल्ला बोल प्रदर्शन

किया जिसके तत्पश्चात दोनों ही गांव सूरजपुर एवं घंघौला में विकास कार्य प्रारंभ हो गए हैं।

करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले गांवों में मूलभूत समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं लेकिन सूरजपुर गांव में जलभराव के कारण ग्रामीण एवं स्कूली बच्चों को रास्ते से गुजरना



दुश्वार हो चुका था वहीं घंघोला गांव में भी दलित बस्ती के पास बना तालाब ओवरफ्लो हो चुका था जिस वजह से तालाब के आसपास के रास्तों एवं घरों तक तालाब का गंदा पानी पहुंच गया।

गंदे पानी एवं जलभराव के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। गंदगी के कारण संक्रमण रोग के खतरा भी बना हुआ था। चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया

कि इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन एवं सूरजपुर घंघौला गांव के ग्रामीणों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने संज्ञान लेते हुए तत्काल दोनों गांवों में तालाब के पानी की निकासी की व्यवस्था एवं सूरजपुर गांव में सीसी रोड बनवाने का कार्य प्रारंभ करा दिया है।

संकट श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष के सामने छलका उद्यमियों का दर्द

विभागीय उदासीनता और प्रताड़ना से उद्यमियों के सामने संकट

संवाददाता, नोएडा

कामगारों और उनके परिवार को कोरोना काल में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए उद्यमियों ने कारोबार में घाटा होने के बावजूद समय पर वेतन दिया, लेकिन विभागीय उदासीनता और प्रताड़ना से उद्यमी परेशान है। उनका यह दर्द शनिवार को सेक्टर-6 स्थित नोएडा एंटरप्राइनेयर्स एसोसिएशन (एनईए) सभागार में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला के साथ आयोजित कार्यक्रम में छलका।

एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने कहा कि विभाग की ओर से उद्यमियों को नोटिस देकर पांच साल का लेखा-जोखा मांगा जा रहा है। कामगारों को दो साल में दिए बोनस की जानकारी मांगी गई है।



उद्यमी फैक्ट्री का संचालन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं के संबंध में उद्यमियों को विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी जाती। इससे कामगार योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि सरकार योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उद्यमी प्रतिबद्ध है।

महत्वपूर्ण बैठक से अधिकारियों के

नदारद होने से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अध्यक्ष सुनील भराला ने उद्यमियों की बातें गंभीरता से सुनी और विभागीय प्रताड़ना के आरोपों की जांच के आदेश दिए।

उन्होंने बताया कि सरकार कामगारों और उनके परिवार को धार्मिक स्थलों की निशुल्क यात्रा कराएगी। एक मई को कामगार मथुरा वृंदावन की यात्रा परिवार के साथ करेंगे।

संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह उद्यमी के साथ समन्वय स्थापित करके अधिक से अधिक कामगारों के फार्म भरवाएं। इस मौके पर श्रम परिषद सदस्य अनुज पांडेय, सहायक श्रमायुक्त शंकर, लघु उद्योग भारती अध्यक्ष एलबी सिंह, एनईए वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोहली, हरीश जोनेजा, धर्मवीर शर्मा आदि मौजूद रहे।

पर्यावरण संरक्षण : यमुना के पानी को शुद्ध करने को नोएडा से मिला बल

नोएडा : कोंडली नाले का पानी यमुना में गिराया जाए। वह पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोएडा प्राधिकरण और सिचाई विभाग को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सीआर बाबू के निर्देशन में कोंडली नाले के गंदे व बदबूदार पानी को प्राकृतिक तरीके से शुद्ध कराने का आदेश दिया है। इसमें नोएडा प्राधिकरण को कृत्रिम वेटलैंड बनाने के लिए राशि खर्च करनी है, जबकि उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग को कृत्रिम वेटलैंड बनाना है। पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को शुरू किया। इसके तहत सेक्टर-51 में नाले में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम वेटलैंड बनाया था, जिसकी सफलता के बाद अब नोएडा में दो जगहों पर नया प्राकृतिक वेटलैंड बनाने का निर्णय लिया गया है।

प्राधिकरण में जल सीवर विभाग के उपमहाप्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि सेक्टर-51 में 500 मीटर के हिस्से में कृत्रिम वेटलैंड बनाने का काम चल रहा है। इसके बाद सेक्टर-137 और एनएसईजेड (नोएडा विशेष आर्थिक जोन) पर नाले के अंदर इसे बनाया जाएगा। जनवरी तक तीनों स्थानों पर कृत्रिम वेटलैंड बन कर तैयार हो जाएंगे। जिस स्थान पर वेटलैंड बनाए जा रहे हैं, उसकी सतह को पथरों से ढक दिया जाएगा। इसके ऊपर मौरंग की परत होगी। इसमें लगाए जाने वाले पौधे फिल्टरेशन, आक्सीडेशन व सेडिमेंटेशन यानी प्रदूषित तत्वों को तल पर लाकर उन्हें खत्म करने की प्रक्रिया करेंगे। यहां चैंबर बनाकर उनमें पानी को रोका जाएगा, जिससे स्लिट नीचे बैठ जाएगी और इसे हटा लिया जाएगा।

40 साल पुराना है कोंडली नाला

कोंडली के अलावा शहर के कई नालों और हरनंदी का पानी नोएडा के सेक्टर-150 स्थित मोमनाथल गांव के पास यमुना में मिल जाता है। इससे यमुना में गंदगी बढ़ती जा रही है।

नोएडा में कंज्यूमर कनेक्ट चैनल से मिलेगी बिजली सुविधाओं की जानकारी

इससे आम उपभोक्ताओं को होगी जानकारी पाने में सहूलियत

नोएडा, संवाददाता ।

विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बिजली से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी के लिए यू-ट्यूब चैनल शुरू किया है। यूपीपीसीएल कंज्यूमर कनेक्ट चैनल के माध्यम से अस्थायी कनेक्शन, वाणिज्यिक व संस्थागत कनेक्शनों के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।

विद्युत निगम के मुख्य अभियंता वीएन सिंह ने बताया कि वर्तमान में लगभग सभी सुविधाएं आनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के अभाव में उपभोक्ता इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में प्रत्येक उपभोक्ता आसानी से बिजली सुविधाओं और योजनाओं का लाभ ले सके, इसके लिए यू-ट्यूब के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।



उधर, नोएडा में उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र अब घर बैठे अपनी डिग्री और मार्कशीट

प्राप्त कर सकेंगे। अब कालेजों को छात्रों का डेटा अवेकस पोर्टल पर अपडेट करना होगा।

मई के पहले हफ्ते में जारी होगी यूपी 16डीई सिरीज

नोएडा। हल्के वाहनों की पंजीकरण सीरिज यूपी 16डीई मई के पहले हफ्ते में जारी होगी। उसी दिन लोग सीरिज के आकर्षक, अति आकर्षक और सामान्य पसंदीदा नंबर बुक कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक सामान्य पसंदीदा नंबर लोग दोपहिया वाहन के लिए एक हजार रुपये और चार पहिया वाहन के लिए पांच हजार रुपये जमा करके बुक कर सकेंगे। वहीं आकर्षक नंबरों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा।

एस एन दुबे मेमोरियल क्रिकेट 25 अप्रैल से होगा

नोएडा। ऑल इंडिया एसएन दुबे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 25 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीम भाग लेगी। प्रतियोगिता में दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर की आठ टीमों में भाग लेंगे। सेक्टर-127 स्थित पायनियर क्रिकेट ग्राउंड पर प्रतियोगिता खेली जाएगी। प्रतियोगिता में सहारनपुर जिला, दिल्ली की तीन टीमें, गौतमबुद्धनगर, फरीदाबाद, की टीम दमखम दिखाएंगी।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-39 के प्राचार्य डा.राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन से सभी छात्रों का पोर्टल पर पंजीकरण मोबाइल नंबर से होगा। सभी का अपना आइडी नंबर होगा। प्रमाणपत्रों के लिए अब कालेजों के चक्कर

नहीं लगाने होंगे। शिक्षकों का डेटा भी पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इससे कालेज में शिक्षकों के बारे में भी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। कालेज में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्रों को पंजीकरण के आदेश दिए गए हैं।

अभिभावक चिंतित, स्कूल प्रबंधन नहीं कर रहे कोविड नियमों का पालन

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता ।

ग्रेनो वेस्ट के टेकजोन-चार स्थित सेंट जेवियर हाई स्कूल प्रबंधन पर अभिभावकों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं कराने का आरोप लगाया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अभिभावक काफी चिंतित हैं। ग्रेनो वेस्ट के सेंट जेवियर हाई स्कूल में अव्यवस्थाओं से नाराज अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की है।

अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बच्चों के लिए एयर कंडीशनर क्लास रूम नहीं है। वाशरूम में हैंडवाश और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं है। अलग-अलग रूट के घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाया जाता है। सेंट जेवियर हाई स्कूल के हर क्षेत्र में अव्यवस्थाओं की भरमार है, जिसकी वजह से कई पैरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, साथ ही व्यवस्थाएं ठीक न होने तक अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की चेतावनी दी है।

अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल टीचर बच्चों को दिए होमवर्क को भी रेगुलर चेक नहीं कर रहे हैं। एक दर्जन से ज्यादा अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के इंतजामों पर सवाल उठाए हैं।

स्कूल की प्रिंसिपल कीर्ति टंडन का कहना है कि एयर कंडीशनर क्लास रूम में बच्चे जो सांस लेते हैं वही छोड़ते हैं, इसी को लेकर क्लासरूम में कोरोना संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वेंटिलेशन के रूप में दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखा जाता है। बिजली बैकअप के लिए स्कूल में डीजी सेट का इंतजाम है।

कोरोना के सक्रिय केस बढ़कर 605 हुए

नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को बीते 24 घंटे में 17 बच्चों समेत कोरोना के 127 नए मरीज मिले हैं। वहीं 90 मरीज स्वस्थ हुए

स्कूल की प्रिंसिपल कीर्ति टंडन का कहना है कि एयर कंडीशनर क्लास रूम में बच्चे जो सांस लेते हैं वही छोड़ते हैं, इसी को लेकर क्लासरूम में कोरोना संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वेंटिलेशन के रूप में दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखा जाता है। बिजली बैकअप के लिए स्कूल में डीजी सेट का इंतजाम है।



हैं। जिले में कोरोना के सक्रिय मरीज 605 हो गए हैं। पिछले पांच दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 100 से अधिक रही। शनिवार को फरवरी के बाद अधिक मरीज देखने को मिले हैं। जिले में कोविड सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी है।

आठ दिन से लगातार प्रदेश में सर्वाधिक नए मरीज गौतमबुद्धनगर में सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही सक्रिय केसों की संख्या में जिला लगातार नंबर एक पर बना है। प्रदेश में कोविड के दो बरसों का इतिहास यदि देखें तो सक्रिय मामलों में लखनऊ लगातार पहले स्थान पर रहा है।

वहीं गौतमबुद्धनगर टाप 10 में शामिल रहा है। जिला सर्विलांस अधिकारी डा.मनोज कुशवाहा का कहना है कि सक्रिय मरीजों में चार संक्रमित मरीज कोविड अस्पतालों भर्ती हैं। इनमें तीन मरीज निजी अस्पताल में, जबकि एक मरीज नोएडा कोविड अस्पताल में भर्ती है।

नौ फर्मों पर लगा 5.65 लाख का जुर्माना

जांच में उद्यान के रखरखाव में मिली थी खामी, की कार्रवाई

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : उद्यान के रखरखाव में खामी मिलने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नौ फर्मों पर 5.65 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि की भरपाई फर्मों को होने वाले भुगतान से की जाएगी।

खराब कार्यों को 15 दिन में दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न होने पर सर्विस लेवल एग्रीमेंट के तहत इन फर्मों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। सेक्टर पाई-एक व दो में पेड़-पौधों की सिंचाई ठीक से न होने के साथ कामगार तय संख्या से कम थे।

आग

शार्ट सर्किट से आग लगना बताया गया

सीएमओ कार्यालय में लगी आग एक घंटे में बुझी

सूचना के बाद दमकल की एक गाड़ी भेजी गई थी। करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया।

संवाददाता, नोएडा : सेक्टर-39 स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार की दोपहर शार्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मचारियों ने एक घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया है। गनीमत रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यहां रखी महत्वपूर्ण फाइल जलकर खाक हो गई।

सीएमओ कार्यालय के कमरा नंबर-5 में जन्म और मृत्यु प्रमाण पक्ष से जुड़े दस्तावेज रखे थे। आग से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर जलकर राख हो गए। हालांकि जो डाटा ईमेल आइडी पर है उसे दोबारा से देखा जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर का डाटा बर्बाद हो गया।

आग की सूचना पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुनील कुमार शर्मा भी पहुंचे



और जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि आग को समय रहते बुझा लिया गया। सीएमओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना के बाद दमकल की एक गाड़ी भेजी गई थी। करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रभावित हुआ कामकाज: सीएमओ कार्यालय में जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के साथ ही महिला थाना स्थित है।

प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहां आते हैं। शुक्रवार को आग लगने के कारण तीनों ही कार्यालय में आने वाले लोगों को बैरंग लौटना पड़ा।

पहले चेतते तो नहीं होती घटना :

पिछले सप्ताह अभियान चलाकर सरकारी कार्यालयों में आग लगने से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया था। इसके बावजूद समस्या को हल कराने के सीएमओ की ओर से प्रयास नहीं किए गए।

कोरोना से सचमुच कितने लोग मरे!

अजीत द्विवेदी

यह यक्ष प्रश्न बन गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मौत हुई? बुधवार 20 अप्रैल की सुबह तक भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक पांच लाख 22 हजार छह लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है। मरने वालों की संख्या के लिहाज से अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत दूसरे स्थान पर है और दुनिया भर में हुई 62 लाख 28 हजार से ज्यादा मौतों में भारत का हिस्सा 12 फीसदी है। लेकिन क्या सचमुच भारत में दो साल की महामारी में इतने ही लोग मरे? यह सवाल इसलिए है क्योंकि दुनिया इस आंकड़े को नहीं मान रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया की तमाम वैज्ञानिक संस्थाएं, जर्नल्स, अखबार, पत्रिकाएं, गैर सरकारी संस्थाएं इस आंकड़े को स्वीकार नहीं कर रही हैं। उनका आकलन है कि भारत में जो संख्या बताई जा रही है उससे आठ गुना ज्यादा यानी करीब 40 लाख मौतें हुई हैं।

अब सवाल है कि दुनिया कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंची और सचाई कैसे सामने आणी? इसके लिए सबसे पहले मौतों का आकलन करने के वैश्विक मॉडल और भारत सरकार के मॉडल के फर्क को समझना होगा। ध्यान रहे भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ और दूसरी विश्व संस्थाओं के मॉडल में कमी निकाली है। लेकिन वह एक सरकारी नजरिया है, जिस पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ या दूसरी वैश्विक संस्थाओं का मॉडल बहुत सरल है। उन्होंने हर साल होने वाली मौतों का औसत आंकड़ा लिया और कोरोना महामारी की अवधि में हुई मौतों की संख्या के आंकड़े को उसके बरक्स रखा। मौत के सालाना औसत आंकड़े से ज्यादा जितनी भी मौतें कोरोना काल में हुई हैं, उनको कोरोना से हुई मौत माना गया। इसके उलट सरकार सिर्फ उन्हीं मौतों को कोरोना से हुई मौत मान रही है, जिनमें मौत का कारण कोविड-19 का



संक्रमण दर्ज किया गया है।

भारत सरकार कह रही है कि डब्ल्यूएचओ का मॉडल गड़बड़ है लेकिन असल में सरकार के मॉडल में कमी है। सरकार मृत्यु प्रमाणपत्र में दर्ज कारण के आधार पर गिनती कर रही है। लेकिन सबको पता है कि भारत में शहरी इलाकों में ही मृत्यु का पंजीयन होता है या मृत्यु प्रमाणपत्र बनाया जाता है। छोटे शहरों और कस्बों में भी ऐसा नहीं होता है। ऊपर से कोरोना महामारी में जितने लोग अस्पताल में इलाज के लिए गए उससे कई गुना ज्यादा लोग अस्पताल नहीं जा सके और घरों में दम तोड़ दिया। गांवों में इस तरह की अनगिनत मौतें हुईं। गंगा किनारे शव दफनाए जाने या गंगा नदी में शव बहाए जाने की तस्वीरें और वीडियो सारी दुनिया ने देखे। क्या ये सारी मौतें सरकार के खाते में दर्ज हुई हैं? देसी और विदेशी दोनों मीडिया ने श्मशानों के बाहर शवों की कतार दिखाई और चिता जलाए जाने के लिए 24 घंटे या उससे भी ज्यादा के इंतजार की खबरें दीं। गैर सरकारी संस्थाओं ने हजारों शवों के अंतिम संस्कार कराए। शहरों के श्मशानों में जगह कम पड़ गई तो शहर से दूर छोटे कस्बों में जाकर लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस तरह की घटनाओं और इनकी मीडिया कवरेज का इशारा भी इस तरफ है कि असली संख्या वह नहीं है, जो सरकार बता रही है।

सरकार मान रही है कि किसी व्यक्ति को

कोरोना का संक्रमण हुआ और जिस दिन संक्रमण का पता चला उसके बाद एक निश्चित अवधि के भीतर उसकी मौत हो गई, वहीं असल में कोरोना से मरा है। क्या इससे वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है? अनेक लोगों की मौत कोरोना का संक्रमण ठीक होने के कई महीने बाद हुई। लांग कोविड की वजह से अभी तक लोग मर रहे हैं। अनेक लोगों में कोरोना संक्रमित होने के लक्षण नहीं दिखे और मौत हो गई। अनेक लोग इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा सके और उनकी मृत्यु हो गई। अनेक लोग दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह से अस्पतालों में जगह नहीं मिली, इलाज नहीं मिल सका और वे मर गए। क्या ऐसी सारी मौतें कोरोना के खाते में नहीं लिखी जानी चाहिए?

ध्यान रहे किसी एक संस्था ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि भारत में 30 या 40 लाख या उससे भी ज्यादा मौतें हुई हैं। अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके अपने अपने निष्कर्ष निकाले हैं और हैरानी की बात है हर निष्कर्ष यहीं बताता है कि भारत में जितनी मौतें बताई जा रही हैं, असल में उससे छह से आठ गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। सबसे पहले दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका 'साइंस' ने जनवरी में बताया कि भारत में कोरोना की वजह से 30 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके बाद दूसरी प्रतिष्ठित पत्रिका 'लैंसेट' ने बताया कि भारत में 40 लाख या उससे ज्यादा मौतें

हुई हैं। इसके मुताबिक दुनिया भर में जो 'एक्सेस डेथ' हुई है यानी हर साल होने वाली औसत मौतों से ज्यादा जो मौतें हुई हैं उनमें से एक चौथाई मौत सिर्फ भारत में हुई है। इसके मुताबिक अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको और रूस में जितनी 'एक्सेस डेथ' हुई है, उससे ज्यादा अकेले भारत में हुई है। भारत के आंकड़ों को लेकर यह भी निष्कर्ष है कि भारत ने वास्तविक संख्या से आठ गुना कम संख्या बताई है, जबकि वैश्विक औसत तीन गुने का है। यानी दुनिया में जितनी संख्या बताई गई है, उससे तीन गुना ज्यादा मौत हुई है, जबकि भारत के आंकड़ों से आठ गुना ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। तीसरी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन की है, जिसका प्रकाशन अभी नहीं हुआ है और जिस पर भारत ने सवाल उठाया है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से 40 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं।

भारत में इन दिनों यह चलन हो गया है कि विश्व संस्थाओं का जो आंकड़ा अपने अनुकूल नहीं होता है उसे खारिज कर दिया जाता है और जिसमें सरकार की तारीफ होती है उसकी वाह-वाही की जाती है। इसी चलन के मुताबिक 'साइंस', 'लैंसेट' और डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल है कि क्या सारी दुनिया की बौद्धिक जमात और विश्व संस्थाएं मिल कर भारत के खिलाफ साजिश कर रही हैं, जो उसके आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर बता रही हैं?

एक तरफ सरकार के लोग बताते हैं कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और अब भारत की बात गंभीरता से सुनी जाती है और दूसरी ओर कह रहे हैं कि सारी दुनिया भारत के खिलाफ साजिश कर रही है? दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। असल में यह कोई साजिश नहीं है, बल्कि यह हकीकत है, जो भारत में भी कुछ अखबारों, पत्रिकाओं, गैर सरकारी संस्थाओं आदि के आकलन से जाहिर हो चुकी है। इसलिए भारत को सचाई स्वीकार करके ज्यादा से ज्यादा पीड़ित परिवारों को राहत मुहैया करानी चाहिए।

बात तो जायज है

यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी धनपतियों पर हुई कार्रवाई से जाहिर हुआ कि टैक्स चोरी कर जुटाए गए धन का पता लगाना संभव है। अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय चाहे, तो वह ऐसा करने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई कर सकता है। यही बात अब दुनिया के 14 मशहूर अर्थशास्त्रियों ने कही है।

यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने अनेक रूसी धनपतियों पर हुई कार्रवाई की है। उनके धन को जब्त कर लिया गया है। इससे यह जाहिर हुआ कि टैक्स चोरी कर या अवैध ढंग से जुटाए गए धन का पता लगाना संभव है। अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय चाहे, तो वह ऐसा करने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई कर सकता है। यही बात अब दुनिया के 14 मशहूर अर्थशास्त्रियों ने कही है। उन्होंने जी-20 देशों से कहा है कि रूसी ऑलगाक्स (अवैध धन इकट्ठा कर धनी लोगों) के खिलाफ चल रही कार्रवाई के साथ ही अब टैक्स हैवेन्स (कर चोरी के अड्डों) पर भी कार्रवाई करें। इन अर्थशास्त्रियों ने जी-20 में शामिल सभी 20 देशों के वित्त मंत्रियों के नाम खुला पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि दुनिया भर के धनी लोग अपने धन को टैक्स हैवेन्स में रखे हुए हैं। टैक्स चोरी से बचने का उन्होंने विस्तृत ढांचा बना रखा है। भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों से कमाए गए धन को भी इसी तरह सुरक्षित रखा जा रहा है। मौजूदा विश्व वित्तीय व्यवस्था के कारण कर चोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिला है।

अब यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी ऑलगाक्स पर हुई कार्रवाई से यह बेनकाब हो गया है कि धनी-मानी लोग किस तरह छिपा कर धन रखने में सफल हो जाते हैं। पत्र में कहा गया है- 'यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि हमें टैक्स हैवेन्स पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पारदर्शिता के उपायों को वहां तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इसके तहत सभी देशों के ऑलगाक्स और टैक्स हैवेन्स में छिपाए गए सभी प्रकार के धन को निशाना बनाया जाना चाहिए। तो अर्थशास्त्रियों ने जी-20 देशों से एक ग्लोबल रजिस्टर (वैश्विक पंजी) बनाने की मांग की है। कहा है कि इस रजिस्टर में मौजूद सभी कंपनियों, संपत्तियों, और उनके स्वामित्व के ढांचे को दर्ज किया जाए।

महाराष्ट्र में राज ठाकरे का इस्तेमाल

भारतीय जनता पार्टी की यह खासियत है कि वह जिस राज्य में चाहे वहां कि किसी पार्टी का राजनीतिक इस्तेमाल कर सकती है। कहीं मुख्यधारा की पार्टी का इस्तेमाल करती है तो कहीं हाशिए पर की पार्टी का। जैसे बिहार में उसने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। चिराग के कारण बिहार में यह स्थिति बनी कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और अब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है।

इसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी का इस्तेमाल किया। हालांकि बसपा की नेता मायावती इससे इनकार कर रही हैं और इसे लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर हमला भी बोला। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी निष्क्रियता का फायदा भाजपा को हुआ।

अब भाजपा महाराष्ट्र में राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है। राज ठाकरे के जरिए भाजपा ने कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा उछाला है। भाजपा और राज ठाकरे दोनों को पता है कि शिव सेना चाहे हिंदुत्व की बात जितनी करे लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहने से उसका हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर हुआ है। इसका फायदा उठा कर राज ठाकरे भी अपनी जगह बना सकते हैं और भाजपा को भी फायदा हो सकता है। सो, राज ठाकरे मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर लगा कर हनुमान चालीसा का पाठ करने के अभियान में लगे हैं तो जून के पहले हफ्ते में अयोध्या जाने का भी ऐलान कर दिया है।

अब वे भी बाबरी विध्वंस आंदोलन का श्रेय लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि उस समय वे भी शिव सेना का ही हिस्सा थे। शिव सेना के लिए यह दुविधा वाली स्थिति है। उसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ होने के बावजूद मुस्लिम वोट मिलने की संभावना कम है और ऊपर से कट्टर हिंदू वोट भी खिसक सकता है।

कॉर्पोरेट की जेब में है 'आजादी'

एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 52 बिलियन डॉलर की रकम आगे कर दी है। फिलहाल, ट्विटर के मौजूदा मालिक मस्क की मंशा को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। मस्क ने हाल ही में ट्विटर की करीब 9 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी। फिर उन्होंने पूरी कंपनी खरीदना का प्रस्ताव रखा।

कॉर्पोरेट नियंत्रित सोशल मीडिया की आजादी का भ्रम तभी टूटना लगा था, जब सोशल मीडिया कंपनियों ने अमेरिकी शासक वर्ग की इच्छा के मुताबिक राजनीतिक आवाजों को दबाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो हाई प्रोफाइल शख्सियत इसका निशाना बनी, वे डॉनल्ड ट्रंप थे। फिर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जिस तरह रूस की बात रखने वाली आवाजों को तमाम सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों से बाहर किया गया, उससे भी यही संकेत मिला कि कॉर्पोरेट जगत के हाथ में सोशल मीडिया आजाद नहीं है। अब

आजादी की पोल अरबपति एलन मस्क ने खोली है। उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए 52 बिलियन डॉलर की रकम आगे कर दी है। फिलहाल, ट्विटर के मौजूदा मालिक मस्क की मंशा को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क ने हाल ही में ट्विटर की करीब 9 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने पूरी कंपनी खरीदने के लिए भी एक प्रस्ताव दिया। तब ट्विटर कंपनी के बोर्ड ने एक नई योजना बनाई, जिससे कंपनी में 15 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदना किसी एक शख्स या संस्था के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा।

इस योजना को रण्वायजन पिलर नाम दिया गया है। मस्क ने ट्विटर को करीब 43 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू पर खरीदने की पेशकश की थी। उसे कंपनी बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया। तब मस्क ने कहा कि वे इस खरीदारी पर 52 बिलियन डॉलर खर्च करने

को तैयार हैं। बहरहाल, ट्विटर ने भले मस्क के प्रस्ताव को फिलहाल ठुकरा दिया है, लेकिन उससे कंपनी के प्रबंधकों में असंतोष पैदा होने के संकेत हैं। इसके जवाब में ट्विटर ने स्पष्ट किया है कि कंपनी बोर्ड को अगर लगता है कि ट्विटर के अधिग्रहण या हिस्सेदारी खरीदने का कोई प्रस्ताव ट्विटर और उसके शेयरधारकों के हित में है, तो वो उन प्रस्तावों पर विचार कर सकते हैं। साफ है, मस्क की मंशा आगे चल कर पूरी नहीं होगी, यह अभी कोई नहीं कह सकता। प्रश्न यह है कि ट्विटर चाहे अपने मौजूदा प्रबंधकों के अधीन रहे या मस्क उसे खरीद लें, क्या अब वह ये दावा करने की स्थिति में है कि उसका असल मकसद मुनाफा नहीं, बल्कि सार्वजनिक संवाद का मंच मुहैया कराना है। और अगर वह मुनाफे के हिसाब से आवाजों को बढ़ाने या दबाने में शामिल बनी रहती है, तो फिर उसे 'सोशल मीडिया क्यों कहा जाना चाहिए?

विश्व पृथ्वी दिवस पर ईशा फाउंडेशन के स्वयं सेवकों ने मृदा संरक्षण के प्रति किया जागरूक

हानिकारक केमिकल के कारण खराब हो रही मिट्टी की सेहत के बारे में बताया गया

नोएडा। पृथ्वी दिवस पर शुक्रवार को मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ साइकिल रैली निकाल कर शहर में विभिन्न स्थान पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति कार्य करने की अपील की गई है।

नोएडा सेक्टर- 21 ए स्थित स्टेडियम में ईशा फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने लोगों को मिट्टी के महत्व के बारे में बताया व हानिकारक केमिकल के कारण खराब हो रही मिट्टी की सेहत के बारे में भी बताया गया। सदगुरु जग्गी वासुदेव की तरफ से 27 देशों में मृदा संरक्षण को लेकर किए जा रहे अभियान के बारे में स्वयंसेवकों ने विस्तार से बताया।

स्वयंसेवकों ने फुटबाल खिलाड़ियों से मिलकर बताया कि मृदा संरक्षण अभियान को लोगों द्वारा समर्थन मिलने पर सरकार की तरफ नीति-नियम में बदलाव किया जाएगा।



लोकतांत्रिक सरकार में जो लोग चाहते हैं उसे सरकार करती हैं। कार्यक्रम में योग व ध्यान के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। मौके पर नीलिमा, शिवा अन्ना, विमल अन्ना सहित मेघा अक्का व अन्य स्वयं सेवक मौजूद रहे।

सामाजिक संस्थानों व वन प्रभाग की तरफ से आयोजित हुआ कार्यक्रम

भविष्य एनजीओ व नोफा की तरफ से आजादी के 75 वे अमृत महोत्सव के उपलक्ष में शहर से 75 लोगों द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैली

का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उत्साह और जागरूकता के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा से करीब 150 लोगों ने जागरूकता रैली में भाग लिया है। नोफा अध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि सेक्टर - 71 रैली से रैली की शुरुआत हुई जो नोएडा स्टेडियम पर समाप्त हुई। पर्यावरण, जल स्रोत, वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ के प्रति जागरूक किया गया। भविष्य संस्था के अध्यक्ष विकास झा, उपाध्यक्ष राहुल पाण्डेय व युवा टीम सरफाबाद सोनू यादव मौजूद रहे। वन प्रभाग की तरफ से इंवेस्ट इन अवर प्लानेट की थीम पर सेक्टर- 14 की रेड लाइट से साइकिल रैली निकाल कर पृथ्वी को प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग जल की कमी और अन्य प्राकृतिक संकट से बचाने के प्रति जागरूक किया गया। प्रभागीय वन अधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव व अन्य मौजूद रहे। नव ऊर्जा युवा संस्था की तरफ से नदी की सफाई एवं पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। संस्था के उपाध्यक्ष संदीप पाठक ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के साथ पौधा रोपण भी किया गया है।

सड़क सुरक्षा सप्ताह नियम तोड़ने पर 128 वाहनों पर कार्रवाई

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता ।

सड़क सुरक्षा सप्ताह के छठें दिन शनिवार को वाहनों और उनके दस्तावेजों की जांच की गई। इसके अलावा बिना हेलमेट व सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले चालकों की जांच की गई। 128 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 89 बिना हेलमेट और 25 बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने व चार मोडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई शामिल है। विभाग से प्राप्त सूचना में बताया गया है कि अभियान अभी जारी रहेगा।

सेक्टर-27, 37, 62, 63, 58,12-22, कालिंदी कुंज रोड, महामाया फ्लाईओवर, किसान चौक और एक मूर्ति के आसपास वाहनों की जांच की गई। इसके अलावा 22 वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया।

इस निरीक्षण के दौरान 21 दोपहिया, 32 चार पहिया और दस भारी वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच की गई। वाहनों का प्रदूषण स्तर मानक के अनुरूप पाए जाने पर उनके प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी कराए गए।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत निगम ने जारी नियंत्रण कक्ष का नंबर

नोएडा। विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शुरू किए गए नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी किया गया। उपभोक्ता बिजली सप्लाई से संबंधित सूचना व शिकायत के नियंत्रण कक्ष के नंबर 0120-2970431 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं को नियंत्रण कक्ष द्वारा जानकारी भी दी जाएगी जिस वजह से बत्ती गुल हुई है और कब तक बिजली जाएगी। बताया गया है कि इससे उपभोक्ताओं को सुविधा होगी।

1912 एप से आसान होगा बिजली समस्याओं का निस्तारण

बिजली कटौती, मीटर में गड़बड़ी, ट्रांसफार्मर में खराबी, बिल में गड़बड़ी की घर बैठे शिकायत कर सकते हैं।

संवाददाता, नोएडा : बिजली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विद्युत निगम ने 1912 एप्लीकेशन को नई तकनीकी के साथ विकसित किया है। अब एक ही समस्या से जुड़ी अलग-अलग शिकायतों पर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल एक संदेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समस्याओं के लिए तय समयसीमा को भी एप अपडेट किया गया है। इसी में विद्युतकर्मियों को शिकायत का

निस्तारण करना होगा।

विद्युत निगम के मुख्य अभियंता वीएन सिंह ने बताया कि 1912 एप 2018 से काम कर रहा है। अब इसमें नए विकल्प जोड़े गए हैं। शिकायतों के निस्तारण में विद्युत निगम और उपभोक्ताओं के बीच समन्वय बनाने में यह काफी मददगार है। अब इसमें कुछ नए विकल्प जोड़े गए हैं। यह चार चरण में काम करेगा। शिकायत, आवंटन, निवारण और फीडबैक। उपभोक्ता अपनी परेशानी निशुल्क शिकायत नंबर 1912 और एप के माध्यम समेत दूसरे माध्यम से कर सकते हैं। एप उसको संबंधित क्षेत्र के एसडीओ, जेई, लाइनमैन, आपरेटर को स्वतः भेज देगा।

उनको तय में समाधान करना होगा। समस्या के कारण के साथ एप पर फीडबैक देना होगा। इसके लिए विद्युतकर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है।

निगरानी बढ़ने से समय पर होगा निस्तारण :

बिजली कटौती, मीटर में गड़बड़ी, ट्रांसफार्मर में खराबी, बिल में गड़बड़ी की घर बैठे शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता को एकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, नाम व पता की जानकारी देनी होगी। इससे बिजली विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निशुल्क शिकायत नंबर पर शिकायतों के निस्तारण को लेकर अब

निगरानी बढ़ गई है। इससे समय पर निस्तारण हो सकेगा।

सेक्टर-18 में शुरू होगा कंट्रोल रूम :

शिकायतों के निस्तारण के लिए सेक्टर-18 स्थित बिजली निगम के कार्यालय में कंट्रोल रूम भी शुरू किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 24 घंटे शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। वर्तमान में मुख्यालय मेरठ स्थित कंट्रोल रूम से ही शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। यहां पर तीन वर्ष पहले कंट्रोल रूम बंद कर दिया गया था। अब फिर से शुरू किया जा रहा है।

निष्कासन अनुशासनहीनता व पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप

पूर्व विधायक सतवीर गुर्जर व नरेंद्र डाढ़ा बसपा से निष्कासित

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गौतमबुद्ध नगर के तीन बड़े नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें दादरी से दो बार विधायक रहे सतवीर गुर्जर, पूर्व जिला पंचायत चेयरमैन वीरेंद्र डाढ़ा व जेवर से बसपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़े नरेंद्र भाटी डाढ़ा शामिल हैं। पार्टी ने तीनों को निष्कासित करने का कारण अनुशासनहीनता व पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताया है। सतवीर गुर्जर ने बसपा से ही राजनीतिक करियर शुरू किया था। दादरी से 2007 व 2012 में लगातार दो बार विधायक रहे। 2017 में वह भाजपा के तेजपाल नागर से चुनाव हार गए थे।

बताया जाता है कि उनके रिश्तेदार व बादलपुर निवासी पूर्व जिला पंचायत चेयरमैन जयवती नागर, उनके पति गजराज नागर व अच्छेजा गांव निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामशरण नागर विधानसभा चुनाव के

दौरान बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। सतवीर गुर्जर के करीबी संजीव त्यागी भी बसपा छोड़कर सपा में चले गए। इससे बसपा हाईकमान सतवीर गुर्जर से नाराज हो गया। पार्टी का मानना था कि पूर्व विधायक अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को सपा में शामिल होने से नहीं रोक सके, इसलिए उन्हें अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सतवीर गुर्जर ने कहा कि वह बसपा के वफादार सिपाही की तरह हैं। शीघ्र बहन मायावती से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे।

पूर्व जिला पंचायत चेयरमैन वीरेंद्र डाढ़ा व उनके छोटे भाई नरेंद्र भाटी डाढ़ा को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। नरेंद्र भाटी जेवर विधानसभा से इसी बार चुनाव लड़े थे। वीरेंद्र डाढ़ा को भी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया था। वीरेंद्र डाढ़ा व नरेंद्र भाटी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के

दौरान बसपा के पदाधिकारियों ने कोई काम नहीं किया। दलित वोट पूरी तरह से भाजपा की तरफ खिसक गया। इसमें जिला संगठन के कई पदाधिकारियों की अहम भूमिका रही। पार्टी कैडर का वोट नहीं मिला। इसी वजह से मतगणना के दो दिन बाद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गौतमबुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी फिर से लखमी सिंह को सौंपी गई है। लखमी सिंह ने बताया कि बहन मायावती के निर्देश पर मेरठ मंडल प्रभाषी प्रदीप जाटव, पूर्व विधान परिषद सदस्य सतपाल पीपला, मनोज जाटव, विजय सिंह व अजीत पाल की संस्तुति पर अयूब मलिक को उपाध्यक्ष, मनवीर भाटी को जिला महासचिव, बाबूलाल गौतम, ओमप्रकाश सिंह व मेघानंद को सचिव, प्रताप सिंह फौजी को जिला खजंची, सुभाष जाटव, जोगिंद्र सिंह, स्वदेश बर्मन व वीरपाल सिंह को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है।

महाअभियान में 4,883 को लगा टीका

नोएडा : कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत शुक्रवार को 4,883 लोगों को कोरोनारोधी टीका लगा। 12 से 14 की आयुवर्ग के 2,011 बच्चों को पहली और 439 को दूसरी डोज लगी। 15 से 17 की आयुवर्ग के 447 को पहली व 459 को दूसरी डोज लगी। 18 पार आयुवर्ग के 233 को पहली व 836 को दूसरी डोज लगी। 60 पार आयुवर्ग के छह को पहली व 48 को दूसरी और 337 को सतर्कता डोज लगी।

जिला टीकाकरण अधिकारी डा.सुनील दोहरे ने बताया कि बच्चों के टीकाकरण के लिए विभाग की ओर से 21 और 22 अप्रैल को विशेष अभियान चलाया गया। जिले के 100 से अधिक स्कूलों में बच्चों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित हुए। बिना मास्क ओपीडी में पहुंचे मरीजों को किया वापस : जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने मास्क अनिवार्य किया है। बावजूद कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं।

शुक्रवार को बिना मास्क जिला अस्पताल

की ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे लोगों को डाक्टरों ने वापस कर दिया। वहीं कई लोगों का पंजीकरण भी नहीं किया गया। ऐसे में कई लोगों ने मौके पर ही जनऔषधि केंद्र से मास्क खरीदकर उसे पहनने के बाद ओपीडी में डाक्टरों से परामर्श लिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मास्क पहनने की व्यवस्था कोरोनाकाल से ही लागू है। अब बिना मास्क आने वाले मरीजों को गेट से ही लौटाया जा रहा है। मरीजों से कहा जा रहा है कि मास्क लगाकर आएंगे। मास्क लगाकर आने पर ही मरीज का इलाज किया जाता है। जीनोम सिक्वेंसिंग को अधिक भेजे जाएंगे सैपल: प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या 100 पार बनने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला डिप्टी सर्विलांस डा.मनोज कुशवाहा का कहना है कि जिले में कोरोना वैरिएंट की पहचान के लिए पिछले दिनों 68 संक्रमितों के सैपल दिल्ली स्थित लैब भेजे थे। इनकी रिपोर्ट शासन के पास है।

दुकान में आग, लाखों का सामान खाक

नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-110 स्थित भंगेल मार्केट में बृहस्पतिवार रात फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की छह गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया। तब तक लाखों रुपये का फर्नीचर जलकर राख हो गया था। रात करीब 10 बजे अग्निशमन विभाग को सूचना मिली थी कि भंगेल मार्केट में फर्नीचर की दुकान में आग लगी है।

लकड़ी का सामान होने की वजह से आग तेजी से फैलकर चार दुकानों तक पहुंच गई। पहले लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी। मार्केट में दुकान करने वाले लोग दमकल की गाड़ियों के देरी में पहुंचने का आरोप लगाया है। सीएफओ अरुण कुमार सिंह बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शार्ट सर्किट के चलते आग लगी है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग से दुकानों में रखा फर्नीचर जल गया। मामले की जांच की जा रही है।

बीच सड़क चलती एक्सयूवी व स्कूटी में आग

सेक्टर-46 स्थित गार्डनिया हाउसिंग सोसायटी के सामने महद्रा एक्सयूवी में आग



लग गई। चालक ने कार से बाहर निकलकर किसी तरह जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। अक्षित टंडन एनआरआइ सिटी में परिवार के साथ रहते हैं। शुक्रवार दोपहर कार से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे थे। जब वह गार्डनिया हाउसिंग सोसायटी के पास पहुंचे तो अचानक कार की एसी के पास में स्पाकिंग हुई। इसी दौरान अचानक कार में आग गई। इसी तरह सेक्टर-33 स्थित इस्कान मंदिर के पास एक स्कूटी में आग लगी गई।

सुप्रीम टावर की 18 वीं मंजिल पर आग

सेक्टर-99 स्थित सुप्रीम टावर में बृहस्पतिवार दोपहर शार्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। फ्लैट में रहने वालों ने सुरक्षाकर्मियों की मदद से कुछ ही घंटे में आग पर काबू पा लिया। एफएसओ संजीव कुमार ने बताया कि सुप्रीम टावर के फ्लैट नंबर 1,803 में आग लगने की सूचना मिली थी।

यहां के सुरक्षाकर्मियों ने निवासियों की मदद से दमकल के आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया था।

आरटीई के तहत दाखिला नहीं तो स्कूलों मान्यता नहीं: बीएसए

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। आरटीई के तहत दाखिला न लेने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने का निर्णय बेसिक शिक्षा विभाग ने लिया है। ऐसे स्कूलों को नोटिस भेजना विभाग ने शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी का



कहना है कि शासन की योजनाओं को सफल होने में दाखिला न लेने वाले स्कूल यदि अड़ंगा लगाएंगे तो उन पर प्रक्रिया के तहत मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में आरटीई (निशुल्क शिक्षा का अधिकार) के तहत निजी 1140 स्कूल पंजीकृत हैं। इन सभी निजी स्कूलों में 18 हजार 29 सीटें हैं। वर्ष 2021-22 में साढ़े चार हजार छात्रों का चयन हुआ था। इसमें निजी स्कूलों ने आधे से अधिक विद्यार्थियों को दाखिला तक नहीं दिया। इस वर्ष 2022-23 सत्र को पहली लिस्ट में 3,399 छात्रों का चयन हुआ है। इस बार भी पिछले सत्र जैसा हाल है।

चयनित स्कूलों में जाने पर छात्रों और अभिभावकों को गेट से ही भगा दिया जाता है। अभिभावक रोज बेसिक शिक्षा कार्यालय से लेकर बेसिक एजुकेशन आफिसर (बीईओ) दफ्तर तक चक्कर लगाकर परेशान हैं। बेसिक शिक्षा कार्यालय से नोटिस भेजने के बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। लगातार शिकायतों पर शासन-प्रशासन योजनाओं के तहत कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। ऐसे में नोटिस की प्रक्रिया के बाद भी न सुधरने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई होगी।

जेवर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार



ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जेवर कोतवाली क्षेत्र के गांव में अवैध रूप से असलहा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने संचालक सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पता चला है कि लंबे समय से संचालित फैक्ट्री से काफी असलहों का निर्यात हो चुका था। मौके से पुलिस ने दो पिस्टल, छह तमंचा, पांच अर्ध निर्मित तमंचा, दस कारतूस, एक गाड़ी सहित अन्य सामान बरामद किया है। पांचों आरोपितों पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी।

सूचना मिली थी कि जेवर क्षेत्र में अवैध असलहा की बिक्री करने वाला गैंग सक्रिय है। गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी। मुखबिर से सूचना के बाद पुलिस ने स्विफ्ट कार से असलहा बेचने निकले चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान मोहल्ला व्यापारियान कस्बा जहांगीरपुर निवासी बिलाल, आसिफ, समीर व शाहरुख के रूप में हुई है। निशानदेही पर पुलिस ने फैक्ट्री संचालक जगवीर निवासी मढैया जेवर खादर को भी गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडे ने बताया कि सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। उनके अपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। तमंचा दो से पांच हजार रुपये में बेचते थे: आरोपितों ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से हथियार की बिक्री कर रहे हैं। एक पिस्टल 38 से 40 हजार रुपये में बेचते थे। तमंचा दो से पांच हजार रुपये में बेचते थे। आरोपितों ने तमंचे की बिक्री अधिक की थी। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। मुखबिर के जरिये पिस्टल खरीदने के लिए पुलिसकर्मी सादी वर्दी में खरीदार बनकर गए थे।

जिले में पूर्व में भी पकड़ी गई है असलहा फैक्ट्री

जिले में अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ने का यह नया मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कासना, बिसरख व बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में भी अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में पकड़ी गई असलहा फैक्ट्री में सबसे अधिक दस कंटी मेड पिस्टल बरामद हुई थी।

अभियान चला तो खुली पोल, 18 बसें सीज

नियम ताख पर रख स्कूलों में दौड़ रहीं टूरिस्ट बसें, 30 बसों का चालान काटा

नोएडा, संवाददाता।

जिले में निजी स्कूल बसें बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। बच्चों को स्कूल बसों में ठूस कर भरा जा रहा है। इसका उदाहरण मुख्यमंत्री के आदेश पर शुक्रवार को शुरू हुए अभियान में भी देखने को मिला।

परिवहन विभाग की जांच में बच्चों को स्कूल ले जा रहे 18 वाहन सड़क पर चलने लायक नहीं मिले, जिन्हें सीज कर दिया गया है। 30 वाहनों के चालान काटे गए। निजी स्कूलों में डेढ़ लाख बच्चे प्रतिदिन बसों से यात्रा करते हैं। स्कूल इनकी सुरक्षा को जोखिम में डाल लापरवाही बरत रहे हैं। बड़ी संख्या में



टूरिस्ट बसें बच्चों को ले जा रही है।

इन बसों की खिड़की पर सुरक्षा बैरियर नहीं लगे हैं। अग्निशमन उपकरण भी नहीं हैं या पुराने हो गए हैं। एआरटीओ प्रवर्तन प्रशासन ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर दौड़ रही स्कूल बसों पर कार्रवाई की जा रही है।

2022-23 सत्र में स्कूलों ने परिवहन शुल्क बढ़ाया है। कुछ स्कूलों ने 75 प्रतिशत परिवहन

शुल्क में वृद्धि की है, जबकि सुविधा और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह बेपरवाह है। क्षमता से अधिक बच्चे बिठाए जा रहे हैं। जिले के कुछ स्कूलों में इसको लेकर अभिभावकों ने विरोध भी किया था।

स्कूलों बसों में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद संवेदनशील मामला है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्कूलों की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। सुविधा और सुरक्षा दोनों स्कूलों की जिम्मेदारी है।

-भूषण शर्मा, अभिभावक
स्कूल ने परिवहन शुल्क बढ़ाया है। उसके बावजूद सुविधाएं सही नहीं मिल रही हैं। बच्चे छुट्टी के दो घंटे के बाद पहुंचते हैं। इसमें प्रशासन को संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
-प्रदीप मिश्र, अभिभावक

महंगाई की भारी पड़ रही मार, कुछ तो करो सरकार

रसोई के हर सामान में महंगाई आ गई है। कोरोना संक्रमण के दौर में संभल ही रहे थे कि सीमित आय के बीच बढ़ी महंगाई से आर्थिक स्थिति अनियंत्रित हो गई है।

- पूजा जैन, निवासी सेक्टर- 75

नोएडा : महंगाई के कारण गृहस्थी पर चारों तरफ से चुनौतियां बढ़ गई हैं। एक तरफ बीते दो वर्ष से कोरोना के चलते आय के स्रोत प्रभावित होने से लोग परेशान रहे। स्थिति में सुधार होते ही चौतरफा महंगाई ने जीवनयापन महंगा कर दिया है। खाद्य समाम्री, रसोई गैस व ईंधन के दाम में बेतहाशा वृद्धि से मध्यम व निम्न आय वर्ग के लोग भंवर में फंस गए हैं।

नौकरी करने वाले लोग वेतन न बढ़ने, रोजगार करने वाले लोग रह-रह कर कोरोना संक्रमण का दौर लौटने के चलते बीते दो वर्ष

चुनाव के बाद महंगाई अनियंत्रित हो गई है। इसके नियंत्रण के विशेष उपाय किए जाने चाहिए। खर्च बढ़ने से बचत ठप हो गई है।

- अर्चना निवासी सेक्टर- 34

में कई बार व्यापार ठप होने की आपाधापी से परेशान हैं। लोगों के लिए घर चलाना दूभर हो गया है। इसके कारण निजी खर्च के साथ घर के जरूरी सामानों तक के दामों में लोगों को कटौती करनी पड़ रही है।

बीते चार वर्ष में खाद्य सामग्री दोगुनी वृद्धि हुई है। चार सदस्यीय परिवार में हर माह चार हजार रुपये खर्च होने वाली रसोई का खर्च पांच-छह हजार तक पहुंच गई है। रसोई गैस के दाम में चार वर्ष में करीब दो सौ रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है। अब रसोई गैस की

थोक सामान की कीमत के बाद फुटकर सामानों में दस रुपये से पचास रुपये तक की बढ़त हो जाती है। किराने के करीब सभी सामानों के दाम पिछले चार वर्ष में तेजी से बढ़े हैं।

-सुशील सिधल, अध्यक्ष, नोएडा डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन।

कीमत प्रति सिलेंडर 947 हो गई है। सीएनजी के दाम में 18 रुपये की बढ़त के साथ 74, पेट्रोल के दाम में 37 रुपये की बढ़त के साथ 105 रुपये हो गए हैं। डीजल 36 रुपये की बढ़त के साथ 97 रुपये प्रति लीटर से अधिक की कीमत पर पहुंच चुका है। इससे यात्रा खर्च में एक हजार से छह हजार तक का भार भी प्रत्येक परिवार में सामान्य रूप से बढ़ा है।

ट्विन टावर में नो फ्लोर पर होंगे विस्फोट

अगले सप्ताह ही प्राधिकरण में सभी की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें टावरों को गिराने की योजना पर चर्चा होगी और उसी बैठक में पूरी जानकारी दी जाएगी।

नोएडा। सुपरटेक के सेक्टर 93 ए में स्थित एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी के ट्विन टावर को 22 मई तक गिराने के लिए एजेंसियां तेजी से काम में जुटी हैं। टेस्ट विस्फोट के बाद अब आने वाली रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिसके बाद ध्वस्तीकरण की पूरी योजना फाइनल की जाएगी।

टावर को गिराने के लिए जुटी टीम के अधिकारियों के अनुसार दोनों टावरों को गिराने के लिए दो विस्फोट होंगे। पहला विस्फोट ग्राउंड फ्लोर, प्रथम, दूसरा, छठवें, 10वें, 14वें, 22वें, 26वें और 30वें फ्लोर पर विस्फोट होगा। दूसरा विस्फोट दूसरे टावर में



समान प्रक्रिया से होगा।

प्रथम विस्फोट के सिक्वेंस 0 से 7.0 सेकेंड का होगा। इसी तरह दूसरा विस्फोट 0 से 3.5 सेकेंड के अंतर पर होगा। विस्फोट के दौरान मलबा परिसर से बाहर नहीं आएगा।

पिलर के चारों ओर हैवी वायर मैश (तारों का जाल) बनाया जा रहा है, जो एक प्रकार की जकड़ बनाता है।

दोनों टावर में विस्फोट के बाद निकलने वाला मलबा आस-पास की इमारतों को

नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचाव के लिए दोनों टावरों के कुछ फ्लोर को जियो टैक्सटाइल फाइबर की शीट से कवर किया जा रहा है। उन्हीं फ्लोर को बाहर से कवर किया जा रहा है, जिनके पिलर में विस्फोट कराया जाएगा। यह कार्य नौ दिन में पूरा होगा।

दोनों टावरों को ध्वस्त करने से पहले 10 अप्रैल को विस्फोट परीक्षण हुआ था। इस दौरान चेन्नई आईआईटी ने छह स्थानों पर कंपन की जांच की थी। इसकी रिपोर्ट अगले सप्ताह तक आने की उम्मीद है।

सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी की एओए के अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया ने कहा कि उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक टेस्ट विस्फोट की सभी रिपोर्ट आ जायेंगी और अगले सप्ताह ही प्राधिकरण में सभी की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें टावरों को गिराने की योजना पर चर्चा होगी और उसी बैठक में पूरी जानकारी दी जाएगी।

जीजा ने पैसे नहीं दिए उधार तो मुंह में बिजली का तार डाल दौड़ाया करंट, मौत

संवाददाता, नोएडा : सेक्टर-73 स्थित सर्फाबाद गांव में जीजा ने एक युवक को उधार पैसे देने से मना किया तो युवक ने बिजली का तार अपने मुंह में लगाकर करंट चालू कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पहुंची सेक्टर-113 कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। मूलरूप से हरदोई निवासी विनय कुमार (24) कुछ दिन पहले सर्फाबाद में रहने वाली बहन के घर आया था। युवक गांव में काम करके अपना खर्च चलाता था। शुक्रवार रात को विनय ने जेब खर्च के लिए जीजा से एक हजार रुपये उधार मांगे

थे। इस पर जीजा ने उससे कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इससे नाराज युवक ने सुबह घर पर अपने मुंह में बिजली का तार लगाया और फिर उसे प्लग में लगाकर करंट चालू कर दिया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज शुरू होने से पहली ही उसकी मौत हो गई।

अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है। कोतवाली प्रभारी शरद कांत शर्मा का कहना है कि प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि युवक का पैसों को लेकर जीजा से विवाद हुआ था। जीजा ने जब पैसे देने से मना किए तो युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। मामले की कोई शिकायत नहीं मिली है।

ठगी बाइक बोट की तर्ज पर ठगी के लिए फंसाते थे शिकार ठगी करने वाली गो वे कंपनी का मास्टरमाइंड कुणाल सेन दबोचा

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: बीटा दो कोतवाली क्षेत्र स्थित एच्छर के समीप से पुलिस ने करीब 10 हजार लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गो वे कंपनी के निदेशक गुरुग्राम निवासी कुणाल सेन को धर दबोचा है। ठगी में कुणाल ने मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। बाइक बोट की तर्ज पर इलेक्ट्रानिक स्कूटी चलवाने के नाम पर एक साल में निवेश रकम को दो गुना वापस करने का झांसा देकर वर्ष 2019 में ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। ठगी में शामिल कुणाल के माता-पिता पूर्व से जेल में बंद हैं। शुक्रवार को कुनाल माता-पिता से मिलने जेल पहुंचा था तभी पुलिस ने उसको धर दबोचा। दरअसल, वर्ष 2019 में गो वे कंपनी का



आफिस दंपती अनिल सेन व मीनू सेन ने खोला। दंपती का बेटा कुणाल कंपनी में निदेशक बना जबकि दंपती सीएमडी के पद पर थे। कुणाल ने ही माता-पिता को इस तरह से स्कीम चलाने का आइडिया दिया। निवेशकों से 62 हजार रुपये इलेक्ट्रिक स्कूटी के नाम पर निवेश करवाए। एक साल में रकम दोगुना वापस करने का झांसा दिया गया।

नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, हरियाणा के लोगों ने कई-कई स्कूटी के नाम पर कंपनी में रकम निवेश कर दी। एक साल तक करीब दस हजार लोगों से करोड़ों की ठगी करने के बाद आरोपित आफिस पर ताला लगाकर फरार हो गए। निवेशक ने आफिस पर धरना दिया तो मामला पुलिस तक पहुंचा। ठगी की घटना को अंजाम देने के करीब एक साल बाद वर्ष 2021 में दंपती अनिल-मीनू गिरफ्तार हुए। अब उनका बेटा कुणाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुणाल अपना मोबाइल मुंबई छोड़ कर आया था, जिससे कि पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन निकाले तो वह मुंबई की आए। पुलिस भी आरोपित से चार कदम आगे

निकली। आरोपित की फ्लाइट टिकट की फोटो व ग्रेटर नोएडा पहुंचने की खास सूचना मुखबिर से प्राप्त कर कुणाल को धर दबोचा। पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके अनिल व मीनू सेन ने हरियाणा के गुरुग्राम में ई रिक्शा का काम शुरू किया था। ठगी को अंजाम देने के बाद से ही कुणाल मुंबई में पुलिस से छिप कर रह रहा था, जबकि दंपती गुरुग्राम में फार्म हाउस में शरण लिए हुए थे। वहां ई रिक्शा मैनुफैक्चरिंग का काम शुरू किया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपितों की संपत्ति जब्त की जाएगी। ठगी के तीनों आरोपित अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। संपत्ति चिह्नित की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अनिल राजपूत, बीटा दो

घर में रस्सी कूदते समय चोट लगने से महिला अध्यापिका की मौत

दादरी, संवाददाता। घर पर पर रस्सी कूदते समय महिला अध्यापिका नियंत्रण बिगड़ने के कारण नीचे गिर गईं। सिर में चोट लगने से उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अध्यापिका का पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस के बताया दादरी में दीपिका (29) सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं। बृहस्पतिवार को सुबह के वक्त वह घर पर रस्सी कूद रही थी। इस बीच नियंत्रण बिगड़ने से जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान सिर में गंभीर चोट आने से बेहोश हो गई। स्वजन ने अध्यापिका को दादरी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

30 जून तक आवेदन करने पर मिलेगी अधिक छूट, बकाया प्रीमियम, प्रतिकर व लीज डीड के विलंब शुल्क पर पेनल्टी से पाएं राहत

संवाददाता, नोएडा :

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के निर्मित भवनों के आवंटियों के लिए यह राहत की खबर है। प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान योजना को लागू कर दिया है। बोर्ड के इस फैसले का कार्यालय आदेश प्राधिकरण ने जारी कर दिया है। प्रीमियम धनराशि, अतिरिक्त मुआवजा या फिर लीज डीड के विलंब शुल्क के बकाएदार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ओटीएस को किया लागू

एकमुश्त समाधान योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी, लेकिन 30 जून तक आवेदन करने पर अधिक छूट मिलेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित निर्मित भवनों के तमाम आवंटी बकाया प्रीमियम व अतिरिक्त मुआवजे का समय से भुगतान नहीं कर सके। लीज डीड में देरी के कारण भी आवंटियों पर विलंब शुल्क लग गए। ऐसे आवंटियों को इन तीनों तरह के बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए बीते 05 अप्रैल को प्राधिकरण बोर्ड ने एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी थी, जिस पर अमल करते हुए प्राधिकरण ने

कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। ओटीएस के तहत आवंटी डिफॉल्ट प्रीमियम धनराशि पर दंडात्मक ब्याज से राहत प्राप्त कर सकते हैं। आवंटी साधारण ब्याज दर पर बकाया धनराशि जमा कर सकेंगे। वहीं, 64 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर समय से न जमा कर पाने वाले आवंटी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ओटीएस के अंतर्गत प्रतिकर की डिफॉल्ट धनराशि पर पेनल इंटेरेस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह लीज डीड के विलंब शुल्क में आवंटी राहत पा सकते हैं। 30 जून तक विलंब शुल्क की 70 फीसदी धनराशि जमा करते हुए आवेदन करने वाले

आवंटियों को 30 फीसदी धनराशि की छूट मिल जाएगी। वहीं, 01 जुलाई से 30 सितंबर तक आवेदन करने वालों को कुल विलंब शुल्क का 80 जमा करना होगा। शेष 20 फीसदी विलंब शुल्क की छूट मिल जाएगी।

ग्रेनो प्राधिकरण की वेबसाइट से ऑनलाइन करें आवेदन

ओटीएस योजना का लाभ पाने के लिए 150 वर्ग मीटर तक के निर्मित भवन होने पर 2000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जबकि 150 वर्ग मीटर से बड़े भवनों पर 5000 रुपये प्रोसेसिंग

फीस लगेगी। एटीएस का लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी अन्य जारी के लिए आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से संपर्क कर सकते हैं। निर्मित भवनों के आवंटियों को राहत देने के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। ओटीएस के अंतर्गत लीज डीड पर विलंब शुल्क, अतिरिक्त मुआवजा और प्रीमियम की बकाया धनराशि पर पेनल्टी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। बकाएदार 30 सितंबर तक तथ प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन जरूर कर दें।